

GSTIN : 23AACCK4616K4ZK
CIN No. L24124RJ2004PLC019288

www.krishnaphoschem.com
accounts@krishnaphoschem.com



KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Date: 08.11.2022

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400051

Dear Sir / Madam

Sub: Submission of Newspaper Cutting of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2022

Please find enclosed herewith extract of newspaper advertisement published for Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2022 at the meeting of the board held on Friday the 04th November, 2022, published in two newspapers viz. The Financial Express (English Edition) and Nafa nuksan (Hindi Edition) on 06th November, 2022 in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information and record.

For Krishana Phoschem Limited

(Priyanka Bansal)
Company Secretary

नफा नुकसान

संपादकीय

केवल ब्याज दर वृद्धि पर्याप्त नहीं, आपूर्ति तंत्र का मांग के साथ संतुलन उचित मूल्य पर आवश्यक

कुभाग्य भारत सरकार व रिजर्व बैंक के बीच सही तालमेल व नीतिगत क्रियान्वयन से ही देश मुद्रा प्रसार दर पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण विश्व आज मुद्रा प्रसार दर के दबाव से त्रस्त है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी करीब करीब ऐसा ही संकेत दे दिया है कि फेडरल रिजर्व ने बैठक में 0.75 प्रतिशत ब्याज दर की वृद्धि की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में यह हस्तक्षेप करना पड़ा है और अब रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वह अपनी नीतिगत विफलता से सरकार को अवगत कराएं तथा दोनों को मिलकर मुद्रा प्रसार दर को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञ केवल विश्व स्तर पर ब्याज दर वृद्धि को ही मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने का एक शस्त्र मानते रहे हैं, लेकिन अनेक बार उन्हें इस संदर्भ में विफलता का भी सामना करना पड़ा है। केवल ब्याज दर वृद्धि ही मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ब्याज दर वृद्धि के बावजूद आज भारत, अमेरिका, यूरोप व ब्रिटेन में मुद्रा प्रसार दर को बढ़ते देखा जा सकता है। ब्याज दर बढ़ने से यह आंकलन किया जाता है कि घरेलू मांग कम होगी। वस्तुओं की उपलब्धता जस की तस रहेगी और इससे मांग व आपूर्ति के स्तर पर संतुलन स्थापित हो जाएगा तथा मुद्रा प्रसार दर कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा अनेक बार संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान संकट के लिए विश्व स्तर पर रूस व यूक्रेन का युद्ध भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके चलते खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यातायात माल ढुलाई प्रभावित हुई है। विश्व स्तर पर समुद्री यातायात के मार्गों में बाधा उत्पन्न हुई है। अमेरिका व मित्र देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से भी परस्पर तनाव बढ़ने के साथ तेल गैस के मूल्य में आपूर्ति बाधित होने से तेजी से वृद्धि हुई है। इससे विष्व स्तर पर उत्पादन व आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस मुद्रास्फीति के अनेक कारण हो सकते हैं। केवल ब्याज दर वृद्धि ही इस स्फीति के

मुद्रा प्रसार नियंत्रण

आकार को कम करने में सक्षम नहीं है। यह तो अब सभी केन्द्रीय बैंक व सरकारों भी महसूस कर रही हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक व मौद्रिक समीक्षा समिति के समक्ष भी अब आत्म विश्लेषण व निरीक्षण का समय आवश्यक आ गया है और इन संस्थाओं को सही अर्थों में सरकार के साथ मिलकर ही निर्णयों का क्रियान्वयन करना होगा। रिजर्व बैंक ने शुरू से ही 2-6 प्रतिशत मुद्रा प्रसार दर का लक्ष्य तय कर रखा है, लेकिन गत छह माह की अवधि में मुद्रा प्रसार दर बढ़कर 7-8 प्रतिशत के स्तर को छू गई है। भारत के संदर्भ में भी खनिज तेल मूल्य वृद्धि, कोविड के दबाव से नागरिकों का गांवों की ओर पलायन तथा देश के औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उत्पादन में गिरावट भी मुद्रा प्रसार दर वृद्धि का कारण बना है। विपक्ष व आलोचक बेशक सरकार पर रुपए की कमजोरी मुद्रा प्रसार दर वृद्धि का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे जान-बूझकर धरातल पर उन कारणों की भी अनदेखी कर रहे हैं, जिनके कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। आपूर्ति तंत्र में बाधा उत्पन्न हुई है। व्यक्तित्व का प्रयत्न प्रभावित हुई है। वर्ष 2020 के दौरान ही लगातार तीन तिमाहियों के दौरान देश की मुद्रा प्रसार दर लक्ष्य से अधिक स्तर को छू गई थी और तत्काल कार्य योजना की शुरुआत तो रिजर्व बैंक व भारत सरकार के स्तर पर परस्पर समन्वय के साथ उसी समय हो जानी चाहिए थी। यह समय संपूर्ण देश के स्तर पर औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होने नागरिकों के पलायन से उत्पन्न हालात का भी असर था। निश्चित रूप से उस समय की मुद्रा प्रसार दर वृद्धि मुख्य रूप से कोविड के दुष्परिणामों के कारण हुई थी। उस समय की मुद्रा प्रसार दर वृद्धि को लेकर आम आमदी भी अधिक उत्तेजित नहीं था, क्योंकि वह कोविड की हकीकत व सरकार की परेशानी को भलि-भांति समझता था। उस समय संपूर्ण विश्व के स्तर पर उदार नीति मुद्रा के प्रसार के संदर्भ में देखी गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक भी इस उदार मुद्रा नीति के ध्वज वाहक

बने थे और भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसी संदर्भ में कार्य करना पड़ा था। संपूर्ण विश्व यह मानता था कि कोविड नियंत्रण के साथ मुद्रा प्रसार दर भी नियंत्रित हो जाएगा। आमतौर पर जब मुद्रा प्रसार दर मांग के कारण बढ़ती है तो मौद्रिक नीति के निर्णय अधिक सार्थक सिद्ध होते हैं। उस समय आपूर्ति तंत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और यही कारण है कि देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नई ऊंचाई को छू गया था और यह लगातार ऊंचाई पर ही रहा है। रिजर्व बैंक ने इसी संदर्भ में शुरूआती स्तर पर पर्याप्त नकद तरलता बाजार में प्रवाहित की, रेपो दर में कटौती भी की और महिनों तक बाजार में अतिरिक्त नकद तरलता ठीक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरह ही भारत में भी 6-8 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रही थी और इसके चलते भारत ने तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में भी कदम रखा और भारत इस कोविड के दबाव से जल्दी बाहर निकलने में भी सफल हो गया था। निश्चित रूप से खाद्य पदार्थों व ईंधन की मुद्रा प्रसार दर ही वृद्धि का मूल कारण रही है और यह वृद्धि मुद्रा नीति में ब्याज दर वृद्धि से प्रभावित नहीं होती है। भारत के उद्योग में भी सर्वाधिक हिस्सेदारी ईंधन व खाद्य पदार्थों की ही रही है। यही कारण है कि केवल ब्याज दर वृद्धि ही मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज देश में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति व सुगम बनने व ईंधन के मूल्य को सहज व सहनीय बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए अगर विश्व स्तर पर विशेशी मुद्रा के उपयोग से खाद्य तेल व खनिज तेल के आयात को बढ़ाने की आवश्यकता है तो यह कार्य किया जाना चाहिए। सरकार को खाद्य पदार्थों व ईंधन पर मूल्य स्तर को घटाकर अन्य विलासिता पर अधिक कर लगाने की नीति अपनानी चाहिए। देश में लॉजिस्टिक तंत्र को और सुधारने की आवश्यकता है। सरकार को उत्पादों की उपलब्धता को सहज बनाने का कार्य करना होगा और उनकी उपलब्धता को कम मूल्य पर सुनिश्चित करना होगा। केवल ब्याज दर वृद्धि मुद्रा प्रसार दर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश आर.के. अग्रवाल एवं सदस्य एम श्रीसा के समक्ष एक याचिका उपबोक्ता कानून की धारा 2(1)(G) तथा 21(b) के अंतर्गत युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरेश कुमार व अन्य संबंधित प्रकरण में विचारार्थ प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि शिकायतकर्ता को एक घरेलू गैस कनेक्शन मिले न था। शिकायतकर्ता ने अनेक बार गैस एजेंसी को इस संदर्भ में पहले ही शिकायत की थी तथा क्लेम के भुगतान हेतु कहा था, लेकिन गैस एजेंसी के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके पश्चात उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की तथा घर में हुए नुकसान व मानसिक तनाव शारीरिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। इसकी सुनवाई के दौरान इंडियन ऑयल की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा गैस एजेंसी ने किसी प्रकार की सिलेंडर की रीफिलिंग करवाता रहा है। सलाह गैस एजेंसी को प्रत्येक सिलेंडर की सफाई पर बीमा प्रीमियम का भुगतान भी प्राप्त होता रहा है। ताकि उसको प्रतिपक्षी बीमा कंपनी से थर्ड पार्टी बीमा सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा गैस एजेंसी समय-समय पर सिलेंडर जांच शुल्क की भी वसूली करती रही है। 19.1.2011 को शिकायतकर्ता को सिलेंडर प्राप्त हुआ था और इसके बदले में गैस एजेंसी को खाली सिलेंडर दे दिया गया था। शिकायत में कहा गया कि गैस सिलेंडर के ऊपर नोजर पर रबड़ सील नहीं थी। शिकायतकर्ता ने समय-समय पर गैस एजेंसी से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, लेकिन हर बार कहा जाने लगा कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। गत 23.1.2011 को जब शिकायतकर्ता की मां खाना पका रही थी तथा पूर्व में लगा हुआ सिलेंडर खाली हो चुका था, तो उसके द्वारा इस नए सिलेंडर को गैस चूल्हे से जोड़ा गया और इसके साथ ही सिलेंडर में आग लग गई तथा संपूर्ण किचन में धुंआ हो गया था। उसी समय पड़सियों के द्वारा सिलेंडर को बाहर निकाला गया, लेकिन इस घटना से शिकायतकर्ता की मां जल गई। शरीर के अनेक हिस्सों पर जलने से शारीरिक पीड़ा हुई। इसी संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। यह भी जानकारी मिली कि इंडियन ऑयल कंपनी तथा गैस एजेंसी इस बीमा

कंपनी के पास बीमति है तथा बीमा कंपनी इस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। यह क्षतिपूर्ति सिलेंडर के ब्लास्ट के कारण हुई है। शिकायतकर्ता ने अनेक बार गैस एजेंसी को इस संदर्भ में पहले ही शिकायत की थी तथा क्लेम के भुगतान हेतु कहा था, लेकिन गैस एजेंसी के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके पश्चात उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की तथा घर में हुए नुकसान व मानसिक तनाव शारीरिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। इसकी सुनवाई के दौरान इंडियन ऑयल की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा गैस एजेंसी ने किसी प्रकार की सिलेंडर की रीफिलिंग करवाता रहा है। सलाह गैस एजेंसी को प्रत्येक सिलेंडर की सफाई पर बीमा प्रीमियम का भुगतान भी प्राप्त होता रहा है। ताकि उसको प्रतिपक्षी बीमा कंपनी से थर्ड पार्टी बीमा सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा गैस एजेंसी समय-समय पर सिलेंडर जांच शुल्क की भी वसूली करती रही है। 19.1.2011 को शिकायतकर्ता को सिलेंडर प्राप्त हुआ था और इसके बदले में गैस एजेंसी को खाली सिलेंडर दे दिया गया था। शिकायत में कहा गया कि गैस सिलेंडर के ऊपर नोजर पर रबड़ सील नहीं थी। शिकायतकर्ता ने समय-समय पर गैस एजेंसी से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, लेकिन हर बार कहा जाने लगा कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। गत 23.1.2011 को जब शिकायतकर्ता की मां खाना पका रही थी तथा पूर्व में लगा हुआ सिलेंडर खाली हो चुका था, तो उसके द्वारा इस नए सिलेंडर को गैस चूल्हे से जोड़ा गया और इसके साथ ही सिलेंडर में आग लग गई तथा संपूर्ण किचन में धुंआ हो गया था। उसी समय पड़सियों के द्वारा सिलेंडर को बाहर निकाला गया, लेकिन इस घटना से शिकायतकर्ता की मां जल गई। शरीर के अनेक हिस्सों पर जलने से शारीरिक पीड़ा हुई। इसी संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। यह भी जानकारी मिली कि इंडियन ऑयल कंपनी तथा गैस एजेंसी इस बीमा

आदेश में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जिला फोरम के द्वारा उचित कारणों व तथ्यों के आधार पर ही उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता कानून उपभोक्ता को शीघ्र ही न्याय उपलब्ध करने के लिए लाया गया है तथा जिला फोरम व राज्य आयोग को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही निर्णय देना होता है। आयोग ने भी कहा कि उपरोक्त घटना पर पुनः विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य धारा 3 अंतर्गत समय पर उपधाराओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आयोग ने उपरोक्त दोनों आदेशों के संदर्भ में कहा कि राज्य आयोग ने उचित कारण व तर्क के साथ आदेश की पुष्टि नहीं की है। आयोग ने कहा कि रिविजन पिटिशर के इस तर्क व आरोप में सच्चाई है कि राज्य आयोग ने बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, उसने सार्वजनिक दायित्व सीमित दायित्व व एलपीजी पैकेज पॉलिसी की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया है। राज्य आयोग ने अपील को खारिज किए जाने के संदर्भ में कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अतः राष्ट्रीय आयोग ने इस अपील को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग के आदेश को खारिज किया और प्रकरण को पुनः राज्य आयोग के पास विचारार्थ रिमांड करने का आदेश दिया तथा आदेश देते हुए कहा कि राज्य आयोग सभी तथ्यों के परीक्षण व अध्यापन के साथ गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करे। राज्य आयोग को तीन माह की अवधि में पुनः आदेश पारित किए जाने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय आयोग ने इस प्रकरण को लेकर अपनी किसी प्रकार की राज्य इस आदेश में नहीं दी।

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णयों की पढ़कर पाठकों के हित के प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें।

-संपादक

हेल्थ • सोसायटी • एज्युकेशन

नफा नुकसान

डिस्कलेमर

नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठकों को कारोबारी जगत में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सूचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बार ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारीयों से मेल नहीं खाता हो व अलग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें ऐसी अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में जिन विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनदाता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावे के लिए विज्ञापनदाता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, न्यूज एजेंसी व संपादकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का सर्वाधिकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान की लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेन्द्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (रजि. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, एसपीएल-4(ए), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित।

संपादक: वैभव कोठारी (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)

फोन: 0141-4011151/52, 0141-3512564

ई-मेल : info@nafanuksan.com

ART OF MANAGEMENT

299

आज के युग में हर व्यक्ति तरह-तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। दुनिया में तरह तरह की समस्या है, लेकिन एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका को समाधान नहीं हो। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान द्वारा समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। जिन्हें तैरना आता है वह पानी से डरते नहीं है एवं पानी में डूबते नहीं है। ऐसे ही जिन्हें ज्ञान होता है वह समस्या से घबराते नहीं एवं अपने ज्ञान से समस्या का समाधान ढूँढ लेते हैं। अगिन लगने पर सभी भली-भांति जानते हैं कि पानी द्वारा भीषण अग्नि को भी शांत किया जा सकता है। ऐसे ही ज्ञान द्वारा अशांत मन को भी शांत किया जा सकता है। अगर मन को शांत नहीं रखेंगे तो तरह-तरह की समस्याओं से त्रस्त हो जाएंगे। अतः मन को शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने मन को शांत रखने के बारे में काफी कुछ लिखा है। योगेश्वर श्रीकृष्ण जीवनभर तरह-तरह की समस्याओं से घिरे रहे लेकिन हर हाल में उन्होंने मन को शांत रखा एवं सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान निकाला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम भी समस्याओं से जकड़े रहे , लेकिन शांत मन से उन्होंने भी हर समस्या का समाधान निकाला। हमें किसी भी हालत में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपने मन को शांत रखना चाहिए एवं हर हाल में स्वयं एवं भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम भगवान से अपनी नजदीकी बनाए रखेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा। रामायण में महान कवि संत तुलसीदास जी ने लिखा है हरि अनंत हरि कृपा अनंता, बिन हरि कृपा मिलें नहीं संता। उन्होंने यह भी लिखा है कि

समय की मांग

रक्तदान डक मंत्र है, कर लें इसका जाप।

नष्ट रक्त: हो जायेंगे, कई जन्म के पाप।।

साधार:-

शारदा-नवल डागा

आज का विचार

आग, आग से नहीं, पानी से शान्त होती है।

अज्ञात

शर्मा ईस्ट इण्डिया हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जयपुर हॉस्पिटल, एस.एम.एच. स्टडियम के पास, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर-302015 (राज.)
फोन: 0141-2742557, 2742266 • **फैक्स:** 0141-2742472 • **CIN:** L85110RJ1989PLC005206
ई-मेल: sharmaeastindia@gmail.com • **वेबसाइट:** www.jaipurhospital.co.in

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रुपये लाखों में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)

S. N.

Particulars

समाप्त तिमाही 30.09.2022

समाप्त तिमाही 30.06.2022

समाप्त तिमाही 30.09.2021

समाप्त अर्द्धवार्षिक वर्ष 30.09.2022

समाप्त अर्द्धवार्षिक वर्ष 30.09.2021

समाप्त वार्षिक वर्ष 31.03.2022

गैर अंकेक्षित

गैर अंकेक्षित

गैर अंकेक्षित

गैर अंकेक्षित

गैर अंकेक्षित

अंकेक्षित

1. परिचालनों से कुल आय

अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)

(कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले)

कर को पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)

(कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से बाद)

कर को बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)

(असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं के बाद)

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर को बाद) के लिए लाभकारी लाभ/ हानि और अन्य व्यापक आय

(कर के बाद)

समता अंश पूँजी

आय प्रति शेयर (रु.10/- प्रति का)

(संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) -

1. मूल

2. तरल

0.24

0.55

0.53

0.79

0.89

2.07

0.24

0.55

0.53

0.79

0.89

2.07

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

68.01

</